कानपुर, बुधवार, 25 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 53, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड भारत-इजरायल रणनीति से पाकिस्तान में हलचल...>Pg12

पीएसआईटी में छात्र की मौत पर बवाल...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

लखनऊ में सियासी भूचाल

बसपा के इकलौते विधायक के घर पर इनकम टैक्स का छापा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार को उस समय हलचल मच गई, जब बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास और कार्यालय पर आयकर विभाग ने तड़के बड़ी छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। राजधानी के गोमतीनगर इलाके में स्थित उनके आवास को सुबह करीब छह बजे सुरक्षा बलों ने घेर लिया। इसके बाद विभाग के 50 से अधिक अधिकारी, जांच टीम और सुरक्षा कर्मी अंदर दाखिल हुए और दस्तावेजों की गहन पड़ताल शुरू की।

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई कथित वित्तीय लेनदेन, निवेश और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच के सिलसिले में की गई। टीम ने आवास के साथ-साथ कार्यालय कक्षों, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस की भी जांच की। कई महत्वपूर्ण फाइलों और हार्ड डिस्क को जब्त किए जाने की सूचना है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इस पूरी कार्रवाई का एक संवेदनशील पहलू यह भी है कि विधायक उमाशंकर सिंह गंभीर कैंसर से पीड़ित हैं। उनके दो बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और चिकित्सकीय परामर्श के चलते वे पिछले कुछ समय से आइसोलेशन में रह रहे हैं। बताया जाता है कि उनके इलाज के लिए नियमित रूप से डॉक्टर और नर्स की टीम आती-जाती है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा कारणों से बाहरी आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाए जाने की चर्चा रही, जिससे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और स्वास्थ्य से जुड़े आवश्यक प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है।

कैंसर से जूझ रहे विधायक इस समय आइसोलेशन में, सियासी गलियारों में इस कार्रवाई पर चर्चा

पहले भी यूपी में हो चुकी हैं बड़ी छापेमारी

- आजम खान - जौहर ट्रस्ट और अन्य परिसरों पर आयकर व ईडी की संयुक्त कार्रवाई, कई दस्तावेज जब्त।
- गायत्री प्रजापति - आय से अधिक संपत्ति और खनन प्रकरण में कई ठिकानों पर छापेमारी।
- धर्म सिंह सैनी - चुनाव बाद करीबी ठिकानों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई।
- ओम प्रकाश राजभर के सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर सर्वे।

क्या संकेत देती हैं ये कार्रवाइयां?

चुनावी और राजनीतिक दौर में एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है। वित्तीय पारदर्शिता और अघोषित संपत्ति पर फोकस। हाई-प्रोफाइल नेताओं पर कार्रवाई से राजनीतिक संदेश भी जाता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उमाशंकर सिंह के मामले में जांच एजेंसियों को क्या तथ्य मिलते हैं और क्या यह कार्रवाई किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा करती है।

सियासी गलियारों में हलचल

बीएसपी के इकलौते विधायक पर हुई इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विपक्षी दल इसे "राजनीतिक दबाव" की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं। गौरतलब है कि गोमतीनगर का यह इलाका राजधानी का पॉश और हाई-प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है, जहां कई वरिष्ठ नौकरशाह और जनप्रतिनिधि रहते हैं। दिनभर चली इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और मीडिया कर्मियों की भीड़ भी जुटी रही। आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की प्रतीक्षा है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

जापान के निवेशकों को सीएम योगी का न्योता

टोक्यो में 'यूपी इन्वेस्टमेंट रोडशो, सुरक्षित माहौल में निवेश का भरोसा

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

टोक्यो। राजधानी जापान के टोक्यो शहर में आयोजित 'यूपी इन्वेस्टमेंट रोडशो' में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जापानी उद्योगपतियों, कारोबारी समूहों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। यही सशक्त संबंध उत्तर प्रदेश और जापानी निवेशकों के बीच औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जितनी बड़ी आबादी, उतनी बड़ी चुनौतियां और उतनी ही अधिक संभावनाएं भी हैं। इन संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हमारी सरकार पिछले नौ वर्षों से लगातार कार्य कर रही है।

मजबूत भारत-जापान रिश्तों के बीच यूपी को बताया 'इकोनॉमी का इंजन

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को तीन गुना और प्रति व्यक्ति आय को भी लगभग तीन गुना बढ़ाने में सफलता हासिल की है। कभी 'बीमारू राज्य' की श्रेणी में गिने जाने वाला यूपी आज भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन बनकर उभरा है और देश में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। रोडशो के दौरान ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों, सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून-व्यवस्था और विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क को निवेश के अनुकूल वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सीएम योगी ने निवेशकों से कहा, ÷आइए, उत्तर प्रदेश के सुरक्षित और पारदर्शी माहौल में निवेश कर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के सपने को साकार कीजिए। हमारी सरकार आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोडशो के समापन पर कई जापानी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुचि दिखाई। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से आगामी महीनों में ठोस निवेश प्रस्ताव और समझौते सामने आएंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

ग्रीन पार्क को दोहरी खुशखबरी

50 करोड़ से होगा कायाकल्प, किराया घटेगा

टी-20, वनडे और आईपीएल की वापसी की जोर-शोर से हो रही तैयारी

» प्रमुख संवाददाता/न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल विकास के लिए 350 करोड़ रुपये के बजट में ग्रीन पार्क के पुनर्विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। पहले चरण में 45 करोड़ रुपये आवंटित कर धनराशि जारी भी कर दी गई है। इसके साथ ही स्टेडियम का किराया कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही ग्रीन पार्क प्रदेश का सबसे कम किराया वाला स्टेडियम बन जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय मैचों, आईपीएल और यूपी टी-20 लीग जैसे बड़े टूर्नामेंटों का आयोजन आसान होगा।

बुधवार को कानपुर सांसद रमेश अवस्थी और मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने स्टेडियम का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जर्जर दीर्घाओं, ड्रेनेज व्यवस्था की कमियों, रखरखाव की स्थिति और अन्य आधारभूत सुविधाओं की खामियों का जायजा लिया गया। सांसद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात कर ग्रीन पार्क के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप बजट में यह प्रावधान संभव हो सका।सांसद ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार स्टेडियम का निरीक्षण किया तो दर्शक क्षमता घटने और सुविधाओं की कमी देखकर चिंता हुई। उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट लेकर तय किया कि कानपुर में फिर से अंतरराष्ट्रीय मुकाबले कराए जाएंगे। उनका कहना है कि ग्रीन पार्क केवल एक स्टेडियम नहीं, बल्कि शहर की पहचान और विरासत है, जिससे हर क्रिकेट प्रेमी का भावनात्मक जुड़ाव है।

मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि किराया कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही आयोजकों को बड़ी राहत मिलेगी और मैचों की संख्या में वृद्धि होगी। पहले चरण में नए प्लेयर्स पवेलियन, आधुनिक मीडिया सेंटर, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाएगा। स्टेडियम को ऑल-वेदर सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि किसी भी मौसम में मैच निर्बाध रूप से हो सकें।

वर्तमान में स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 27,400 दर्शकों की है, जिसे बढ़ाकर 50,000 तक करने की योजना है। जर्जर सी-स्टॉल और बी-जनरल स्टैंड को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई दीर्घाएं विकसित की जाएंगी।

विकास कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रीन पार्क में एक बार फिर वनडे, टी-20 और आईपीएल जैसे बड़े मुकाबलों की मेजबानी का रास्ता साफ होगा। यह पहल न केवल क्रिकेट को बढ़ावा देगी, बल्कि युवाओं में खेल के प्रति उत्साह जगाएगी, पर्यटन को प्रोत्साहन देगी और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। क्रिकेट प्रेमियों को अब उस दिन का इंतजार है, जब ग्रीन पार्क एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की रौनक से जगमगाएगा।

> **ग्रीन पार्क हमारे शहर की शान है। इसका विकास हमारी प्राथमिकता है। हम संकल्पित हैं कि यहां फिर से बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले होंगे और कानपुर की पहचान नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।**
>
> **रमेश अवस्थी, सांसद कानपुर लोकसभा**

हीरक जयंती वर्ष में मनाया गया ईएसआईसी का स्थापना दिवस

75 वर्षों की सेवा यात्रा का उत्सव, अधिकारियों व अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ

» प्रमुख संवाददाता/न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। यह अवसर निगम की 75 वर्षों की उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवा यात्रा का प्रतीक रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री विशाल कुमार खरे, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्री गौतम झा, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्री के.सी. झा, क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम उत्तर प्रदेश, श्री संजय कुमार, संयुक्त निदेशक ईएसआईसी तथा श्री राकेश रंजन, सहायक निदेशक एनसीडीए द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

अपर निदेशक श्री के.सी. झा ने अपने संबोधन में निगम की स्थापना से लेकर अब तक की उल्लेखनीय उपलब्धियों

पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी आधुनिक तकनीक एवं पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इस मौके पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निगम की उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रस्तुति दी। समारोह में कानपुर के प्रतिष्ठित उद्यमी बलराम नरूला, राष्ट्र मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सचिव उमेश शुक्ला, बीएमएस के महामंत्री अनिल उपाध्याय तथा सेवानिवृत्त अपर आयुक्त आरके शुक्ला को शॉल एवं पुष्प भेंट कर क्षेत्रीय निदेशक श्री के.सी. झा द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

❍ जेसीबी से टक्कर के बाद बीसीए छात्र की चली गई जान ❍ सुरक्षा लापरवाही को लेकर साथी छात्रों का उग्र प्रदर्शन

पीएसआईटी में छात्र की मौत पर बवाल

प्रमुख संवाददाता

कानपुर। पनकी स्थित प्रनवीर सिंह इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (पीएसआईटी) में एक छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद बुधवार को परिसर में व्यापक हंगामा और तोड़फोड़ हुई। आक्रोशित छात्रों ने कैंपस में प्रवेश कर प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी की तथा कई स्थानों पर दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

घटना सोमवार शाम की है। बीसीए अंतिम वर्ष के छात्र प्रखर सिंह (21) की निर्माण कार्य के दौरान खड़ी जेसीबी मशीन से बाइक टकराने पर गंभीर चोटें आई थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कॉलेज के पीछे वाले मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन के गुजरने से धूल का गुबार उठा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और बाइक अनियंत्रित होकर जेसीबी से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को पहले कल्याणपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। बाद में सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान देर रात लगभग दो बजे उसकी मृत्यु हो गई। चिकित्सकों के अनुसार, आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची थी। मृतक प्रखर सिंह रतनलाल नगर का निवासी था। उसके पिता प्रभाकर सिंह खाद व्यवसाय से जुड़े हैं। परिजनों ने बताया कि वह प्रतिदिन की भांति कॉलेज गया था और छुट्टी के बाद घर लौटते समय यह दुर्घटना हुई।

छात्रों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए थे, न ही मार्ग पर चेतावनी संकेतक या सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी। वहीं, संस्थान के ग्रुप डायरेक्टर प्रो. मनमोहन शुक्ला ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना परिसर से लगभग 200 मीटर दूर हुई, इसलिए इसे कैंपस के भीतर की घटना नहीं माना जा सकता। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है और परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

एक नजर में...

- बीसीए अंतिम वर्ष के छात्र प्रखर सिंह की दुर्घटना में मृत्यु
- निर्माण स्थल के पास खड़ी जेसीबी से बाइक टकराई
- छात्रों ने सुरक्षा लापरवाही का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन
- कैंपस में तोड़फोड़, कई थानों की पुलिस तैनात
- प्रबंधन का दावा, घटना कॉलेज परिसर से बाहर हुई

वंदे भारत एक्सप्रेस का ब्रेक जाम, कानपुर सेंट्रल पर एक घंटे से अधिक रुकी रही

प्रमुख संवाददाता

⇨ प्लेटफॉर्म-1 पर तकनीकी खराबी से यात्रियों को हुई परेशानी, टीम ने मौके पर किया निरीक्षण

कानपुर। वाराणसी से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (22415) बुधवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय से अधिक देर तक खड़ी रही। ट्रेन के ब्रेक सिस्टम में अचानक आई खराबी के चलते उसे प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन सुबह लगभग 9:26 बजे स्टेशन पर पहुंची थी। निर्धारित ठहराव के बाद जब ट्रेन को आगे बढ़ना था, उसी दौरान ब्रेक जाम होने की समस्या सामने आई। चालक दल द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद तकनीकी खराबी की पुष्टि की गई, जिसके बाद रेलवे के अभियंताओं और तकनीकी कर्मचारियों की टीम को तत्काल मौके पर बुलाया गया।

करीब एक घंटे से अधिक समय तक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने से यात्रियों में बेचैनी और नाराजगी देखी गई। कई यात्रियों ने देरी को लेकर चिंता जताई, वहीं कुछ यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की। स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने यात्रियों को स्थिति से अवगत कराया और समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

तकनीकी टीम द्वारा ब्रेक सिस्टम की गहन जांच की गई और आवश्यक मरम्मत कार्य किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी मानकों की जांच के बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया गया। घटना के कारण ट्रेन के आगे के स्टेशनों पर पहुंचने के समय में भी विलंब होने की संभावना जताई गई है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि तकनीकी खराबी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या की पुनरावृत्ति न हो।

प्लेटफॉर्म पर लावारिस मिली नवजात, कहां है मां की ममता!

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

⇨ कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लाल कपड़े में लिपटी मिली बच्ची, अस्पताल में भर्ती

कानपुर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली, जिसे जन्म देने के बाद कोई मां छोड़कर चली गई।

जानकारी के मुताबिक, स्टेशन परिसर के निरीक्षण के दौरान वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की नजर प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन के बीच लाल कपड़े में लिपटी एक नवजात पर पड़ी। बच्ची को देखते ही स्टाफ ने उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

नवजात की हालत को देखते हुए तुरंत उसे लोको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है।घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद यात्रियों का दिल भर आया और हर कोई इस अमानवीय कृत्य पर सवाल उठाता नजर आया। वहीं, प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर नवजात को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर कौन फरार हुआ।सहायक वाणिज्य प्रबंधक पवन कुमार के अनुसार, बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया है और मां की पहचान के लिए जांच जारी है।

फरवरी में जून जैसी तपिश, कानपुर में पारा 30 के पार

सीएसए के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, गर्मी और बढ़ने के आसार

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीएसएआई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। फरवरी माह में इस स्तर का तापमान आमतौर पर असामान्य माना जाता है।

न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक है। दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड का मिश्रित असर देखने को मिल रहा है। सापेक्ष आर्द्रता अधिकतम 93 प्रतिशत तथा न्यूनतम 23 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे सुबह हल्की नमी और दोपहर में शुष्क गर्मी का अहसास हुआ। हवा की औसत गति 2.5 किमी प्रति घंटा रही और हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम रही।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों तक आसमान साफ रहेगा और वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी प्रकार तापमान में बढ़ोतरी जारी रही तो रबी फसलों, विशेषकर गेहूं की पैदावार पर असर पड़ सकता है।

एक सप्ताह में ऐसे चढ़ा पारा

तारीख	अधिकतम	न्यूनतम
19 फरवरी	27.8	10.9
20 फरवरी	28.4	11.2
21 फरवरी	29.1	11.5
22 फरवरी	29.7	12.0
23 फरवरी	30.0	12.3
24 फरवरी	29.8	12.5
25 फरवरी	30.5	12.7

(नोटः तापमान डिग्री सेल्सियस में)

सड़क बनी अखाड़ा, दबंगो ने ऑटो चालक को लाठी से पीटा

शिवली में दबंगों का आतंक, ऑटो चालक को पीटने का वीडियो वायरल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के बैरी सवाई गांव में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देने का मामला सामने आया है। दबंगों ने एक ऑटो चालक को बीच सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने ऑटो चालक को सड़क पर रोककर लात-घूंसों और थप्पड़ों से जमकर पीटा। चालक खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दबंगों के सामने बेबस नजर आया।

पीड़ित अनिल

आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने हिम्मत कर बीच-बचाव तक की कोशिश भी नहीं किया। घटना में घायल चालक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने उसे निशाना बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल वह डरा-सहमा है और परिवार के साथ असुरक्षित महसूस कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कानपुर देहात पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि दबंगों के हौसले पस्त हों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा ना किया जा सके।

कोडीन युक्त कफ सिरप गिरोह पर बड़ा शिकंजा, 13.53 करोड़ की संपत्ति की गई सील

सिंडिकेट इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर मनोज यादव, पत्नी और बेटे की संपत्तियां जब्त

» सात बैंक खातों में 86.51 लाख रुपये फ्रीज, रियल एस्टेट निवेश की परतें खुलीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

वाराणसी। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में पुलिस और प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.53 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां सील कर दी हैं। यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की। एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी मनोज यादव और उसके नेटवर्क के खिलाफ विस्तृत आर्थिक जांच के बाद यह कदम उठाया गया है।जांच में सामने आया कि सिंडिकेट इंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर मनोज यादव फर्जी ई-वे बिल तैयार कर पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर रहा था। इस अवैध नेटवर्क को वह अपने सहयोगी शुभम जायसवाल के साथ मिलकर संचालित करता था। पुलिस के अनुसार, दवा की आड़ में नशीले कफ सिरप की बड़ी खेप विभिन्न स्थानों तक पहुंचाई जाती थी।मनोज यादव एलएमएस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भी है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि को रियल एस्टेट में निवेश किया गया। प्रशासन ने 12.66 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। इसमें सूजाबाद स्थित गोदाम, ईश्वरगंगी के चंपाबाग टॉवर का फ्लैट, पिंडरा, राजातालाब और सारनाथ क्षेत्रों में खरीदी गई जमीनें शामिल हैं। सूजाबाद का गोदाम पूर्व में ही सील किया जा चुका था।कार्रवाई केवल आरोपी तक सीमित नहीं रही। उसकी पत्नी मीनू यादव और बेटे लक्ष्य यादव के नाम पर दर्ज संपत्तियों को भी जब्ती की जद में लिया गया है। वित्तीय जांच के दौरान एक्सिस बैंक समेत सात अलग-अलग बैंक खातों में जमा 86.51 लाख रुपये फ्रीज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह रकम अवैध कारोबार से अर्जित की गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, पूरे नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों की गहन पड़ताल की जा रही है। पूर्वांचल में सप्लाई चेन, फर्जी दस्तावेजों और निवेश के अन्य स्रोतों की जांच जारी है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जांच के दायरे में आने वाले अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।

धुएं की चादर में ढका पनकी, सुबह-सुबह सांस लेना हुआ मुश्किल

» पनकी धाम रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में 2 घंटे तक छाया जहरीला धुआं, यात्री और राहगीर परेशान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।कानपुर के पनकी क्षेत्र में बुधवार सुबह जहरीले धुएं की चादर ने लोगों की सांसें थाम दीं। सुबह करीब 6 बजे से 7-45 बजे तक पनकी धाम स्टेशन समेत 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में घना धुआं छाया रहा, जिससे आम नागरिकों, राहगीरों और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री भी इस प्रदूषण से परेशान नजर आए।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिली। आरोप है कि पनकी हाईवे की ओर खुलेआम कूड़ा और प्लास्टिक जलाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल रहा है। इसके साथ ही पनकी पावर प्लांट की चिमनियों से निकलने वाली राख और धुआं प्रदूषण को और गंभीर बना रहा है।इस धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। रतनपुर, शताब्दीनगर, एलिडिको, गंभीरपुर और कपिली जैसे इलाकों में हालात और भी खराब बताए जा रहे हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि कूड़ा जलाने पर सख्ती से रोक लगाकर आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों—जैसे स्मार्ट डस्टबिन, कम्पोस्ट मशीन और एआई आधारित सिस्टम—को लागू किया जाए तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

फिलहाल स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है।

सम्पादकीय

डिजिटल खतरे को भी आतंकवाद माना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट के दौर में लगातार घातक और ग्लोबल होते आतंकवाद से निपटना देश-दुनिया की बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के चलते दुनिया का कोई कोना आज आतंकवाद से अछूता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आतंकवाद से मुकाबला करने वाला हमारा तंत्र तकनीक और संसाधनों के दृष्टिकोण से उन्नत नहीं है, जिसके चलते अपराधी पुलिस व सुरक्षा बलों पर इक्कीस पड़ते हैं। संगठित अपराधी गिरोह हवाला और अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर सरकारों को चुनौती देने लगे हैं। इस संकट के आलोक में भारत सरकार ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। भारत सरकार ने अब आतंकवाद के खिलाफ जंग में नई राष्ट्रीय नीति और रणनीति 'प्रहार' को सिरे चढ़ाने की घोषणा की है। 'प्रहार' अर्थात? 'प्रिवेंशन, रिस्पांस एंड हेल्थिंग अप्रोच टू एंटी-टेररिज्म।' गृह मंत्रालय द्वारा तैयार इस आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति में पहली बार डिजिटल खतरों को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही के दिनों में देश के भोले-भाले नागरिकों को जिस तरह हाउस अरेस्ट करके सरेआम लूटा गया, उससे देश के सभ्य समाज में भय व्याप्त है। लोगों की जीवनभर की जमापूंजी और सेवानिवृत्ति लोगों के पूरे सेवाकाल की बचत पर जिस तरह ऑनलाइन डाका डाला जा रहा है, उसे देखते हुए डिजिटल खतरों को आतंकवाद की श्रेणी में रखना वक्त की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि डिजिटल अपराधों से आतंक फैलाने वालों को आतंकवादियों जैसी सजा देने का प्रावधान हो। हाल ही के दिनों में देश में साइबर हमले और आपराधिक हैकिंग के मामले भी खासे बढ़े हैं। यह स्वागतयोग्य है कि नई आतंकवाद विरोधी नीति में दुनिया के काले कारोबार की कुख्यात धारा डार्क वेब, क्रिप्टो मायाजाल आदि उन्नत तकनीकों द्वारा अपराध जगत को सींचने वाले वित्तपोषक तंत्र से निपटना भी नई आतंकवाद विरोधी नीति का लक्ष्य होगा, जो आज देश में आतंकवाद पोषण का जरिया बन रहा है।निस्संदेह, हाल ही के दिनों में सीमा पार से जारी ड्रोन हमले और साइबर आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है।

यदि खतरे को समय रहते भांपते हुए तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके तो नागरिकों के हित सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिये जरूरी है कि नागरिक सुरक्षा में लगी पुलिस, सुरक्षा बलों तथा अन्य आंतरिक क्षमताओं को एकीकृत किया जाए।

साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले संगठनों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ जारी इस रणनीति में आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस सूचनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, सुरक्षा बलों को उन्नत हथियार उपलब्ध कराने, नई तकनीक से लैस करने, पुलिस, एनएसजी व केंद्रीय सुरक्षा बलों में समन्वय से तत्काल प्रतिक्रिया देने, सुरक्षा एजेंसियों के आधुनिकीकरण व प्रशिक्षण से आतंक पर प्रहार की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहली बार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भी आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे में शामिल किया गया है।

समाज के लिए खतरनाक है 'संतों के चोले में अपराधियों की घुसपैठ'

श्याम सिंह पंवार (वरिष्ठ पत्रकार)

भारतीय समाज में सदियों से संतों, साधुओं और बाबाओं को आस्था का केंद्र माना जाता रहा है। काला, श्वेत अथवा भगवा वस्त्र, जटा, रुद्राक्ष की माला और हरि ओम का उच्चारण-ये सब देखकर आम जनमानस का मन श्रद्धा से भर उठता है। लेकिन आज का यथार्थ यह है कि इसी भगवा चोले को ढाल बनाकर कई अपराधी समाज में घुसपैठ कर चुके हैं। यह घुसपैठ सिर्फ व्यक्तिगत ठगी तक सीमित नहीं, बल्कि बलात्कार, हत्या, जबरन धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, नाबालिगों के शोषण और देश-विरोधी गतिविधियों तक फैल चुकी है। यह एक गंभीर सामाजिक कैंसर है जो आस्था के नाम पर समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है अर्थात एक आस्था की पहचान एक पवित्र चोला अपराध का मुखौटा बनता दिख रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में साधुओं के नाम पर कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं, जिनका नाम बलात्कार, हत्या, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, ठगी और जमीन हड़पने आदि मामलों में जुड़ा पाया गया।

अभी हाल ही की बात करें तो उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत सैकड़ों फर्जी साधु गिरफ्तार हुए, जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल थे जो संत बनकर लोगों को ठग रहे थे और संभवतः अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त थे।

ऐसे अनेक उदाहरण बताते हैं कि अपराधी जानबूझकर संत का लिबास पहनते हैं क्योंकि भारतीय समाज में आस्था बहुत गहरी है। इस ओर जांच-पड़ताल कम होती है। भक्तगण, अंध-श्रद्धा में करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। वहीं आश्रमों में गोपनीयता भी आसानी से मिल जाती है।

पुलिस और प्रशासन भी शुरू में सतर्क नहीं होते, क्योंकि फ़संतफ़ का नाम जुड़ा होता है।

लेकिन जब कोई फर्जी बाबा बलात्कार या हत्या जैसा अपराध करता है, तो सच्चे संतों पर भी संदेह की नजर पड़ती है। इससे पूरी संत-परंपरा बदनाम होती है। कुछ मामलों में विदेशी तत्व (जैसे घुसपैठिए) संत बनकर सक्रिय होते पाए गए हैं। यह खतरनाक ट्रेंड है। कई बार अनुयायी अपराधी के बचाव में सड़कों पर उतर आते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं—यह लोकतंत्र और कानून के लिए चुनौती है।

ऐसे में जरूरी है कि फर्जी संतों/बाबाओं के खिलाफ स्पेशल कानून बने, जिसमें आश्रमों का रजिस्ट्रेशन, आय-व्यय का ऑडिट अनिवार्य हो। फर्जी बाबाओं के प्रति जागरूकता करते हुए स्कूल-कॉलेज, ग्राम सभाओं में अंधविश्वास के खिलाफ शिक्षा दी जाए। जांचो, फिर आस्था करो का संदेश फैलाया जाए।

बड़े आश्रमों की नियमित जांच, खासकर जहां बड़ी संख्या में नाबालिग या महिलाएं रहती हैं।

मुख्यधारा की मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि सनसनी फैलाने के बजाय सत्य की पड़ताल करे, ताकि सच्चे संतों की पहचान बनी रहे।

संतों का चोला पवित्र होता है, लेकिन जब अपराधी उसमें घुसपैठ कर लेते हैं तो यह समाज के लिए खतरा बन जाता है। सच्ची आस्था कभी अंधी नहीं होती! वह विवेक के साथ चलती है। लेकिन, अब समय आ गया है कि हम भगवा देखकर आंखें बंद न करें, बल्कि विवेक की आंखें खोलें। क्योंकि अंध-श्रद्धा से बड़ा अपराध कुछ नहीं। जब तक फ़संतों के चोले में अपराधियों की घुसपैठ पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक समाज सुरक्षित नहीं हो सकता।

हर स्तर पर कानूनी विशेषज्ञों को जोड़ने की सिफारिश

आतंकवाद

निरंजन भंडारी

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता। लेकिन यह भी उतनी ही स्पष्टता से दर्ज किया गया है कि सीमा पार से प्रायोजित जिहादी आतंकी संगठन और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहे हैं।भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सोमवार को देश की पहली समग्र आतंक विरोधी नीति जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ संघर्ष एक संगठित और आक्रामक ढांचे के तहत लड़ा जाएगा। इस नीति का नाम रखा गया है प्रहार। नाम ही संकेत दे रहा है कि यह नीति रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रतिघात और प्रतिकार की सोच पर आधारित है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेज में साफ कहा गया है कि भारत को सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के साथ-साथ साइबर हमलों, ड्रोन के दुरुपयोग और उभरती तकनीकों के जरिये हो रहे हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि अपराधी हैकर और कुछ राष्ट्र लगातार साइबर हमलों के जरिये भारत को निशाना बना रहे हैं। यह खतरा अब केवल बंदूक और बारूद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि की-बोर्ड, कोड और क्रिप्टो वॉलेट तक फैल चुका है।नीति में यह रेखांकित किया गया है कि भारत जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर आतंकी खतरों से जूझ रहा है। बिजली, रेल, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता को मजबूत किया गया है ताकि राज्य और गैर राज्य तत्वों की साजिशों को विफल किया जा सके। यह स्पष्ट संकेत है कि अब आतंक के खिलाफ केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि रणनीतिक

तैयारी पहले से की जाएगी।इसे भी पढ़ेंः बिना वर्दी वाले हीरो अ4ह्यश्ष्ठ ष्ठश्द ने दिखाई अद्भुत वीरता, पैर में गोली लगने के बावजूद सीधे आतंकियों से भिड़ गयादस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता। लेकिन यह भी उतनी ही स्पष्टता से दर्ज किया गया है कि सीमा पार से प्रायोजित जिहादी आतंकी संगठन और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहे हैं। अल कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों का नाम लेते हुए नीति में कहा गया है कि ये संगठन स्लीपर सेल के जरिये भारत में हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहे हैं।विशेष चिंता का विषय ड्रोन और रोबोटिक तकनीक का दुरुपयोग है, खासकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में। हथियार और मादक पदार्थ गिराने से लेकर आतंकी हमलों की साजिश तक, तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन टूल, डॉर्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट के जरिये फंडिंग और प्रचार का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। नीति इस डिजिटल युद्ध को पहचानते हुए सीबीआरएनईडी यानी रासायनिक, जैविक, विकिरण, परमाणु, विस्फोटक और डिजिटल सामग्री तक आतंकी पहुंच को रोकने की चुनौती पर जोर देती है।गृह मंत्रालय ने जांच की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कानूनी विशेषज्ञों को जोड़ने की सिफारिश की है ताकि एफआईआर से लेकर अभियोजन तक केस मजबूत बन सके। यह कदम आतंक के खिलाफ अदालतों में निर्णायक सजा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।कट्टरपंथ के मुद्दे पर भी नीति स्पष्ट है।

अक्सर देखने में आता है कि आतंकी संगठन भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में चरणबद्ध पुलिस प्रतिक्रिया, कानूनी कार्रवाई और पुनर्वास कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। समुदाय और धार्मिक नेताओं की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए कहा गया है कि जागरूकता और संवाद के जरिये युवाओं को भटकने से रोका जाएगा। जेलों में भी डि रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है।यह नीति केवल घरेलू ढांचा नहीं है। इसमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की भी आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि आतंक का नेटवर्क सीमाओं से परे फैला हुआ है।

झोलाछापों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, चौबेपुर में दो क्लीनिक सील

○ अचानक हुई छापेमारी से मचा क्लीनिक संचालकों में हड़कंप ○ संदिग्ध उपचार में हुई तीन मौतों के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग

स्वराज इंडिया ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर (कानपुर)। संदिग्ध इलाज से हुई तीन मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने चौबेपुर कस्बे में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। अवैध क्लीनिकों और मानकविहीन मेडिकल स्टोरों पर शिकंजा कसने निकली टीम ने बिठूर रोड स्थित भट्ठा कोठी क्षेत्र, जीटी रोड के किनारे पिपरी रोड के सामने, कस्बा चौबेपुर के टू मार्केट समेत कई स्थानों पर जांच की।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबेपुर के प्रभारी डॉ. यशोवर्धन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम सबसे पहले भट्ठा कोठी स्थित एक पॉली क्लीनिक पहुंची, जहां संचालक अनुपस्थित मिला और आवश्यक दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इसके बाद टीम जीटी रोड स्थित एक अन्य क्लीनिक पर पहुंची, जहां पंजीकरण संबंधी कागजात नहीं दिखाए जा सके। कस्बा चौबेपुर के टू मार्केट में संचालित एक दवाखाने में भी अभिलेखों के अभाव में सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में भट्ठा कोठी क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान फार्मासिस्ट मौके पर नहीं मिला। टीम ने संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति के दवा वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है।

कार्रवाई की सूचना फैलते ही कई संदिग्ध क्लीनिकों पर ताले लटक गए। स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अपंजीकृत अथवा नियम विरुद्ध चिकित्सा सेवाएं देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा।

दस्तावेज नहीं तो क्लीनिक बंद

जांच के दौरान कई स्थानों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र, चिकित्सकीय डिग्री और अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगली जांच में भी कागजात न मिलने पर सीधे सीलिंग और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल स्टोरों पर भी कड़ी नजर

दवा दुकानों की जांच में फार्मासिस्ट की अनिवार्य मौजूदगी पर विशेष जोर दिया गया। विभाग ने साफ किया है कि नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन की संस्तुति सहित कठोर कदम उठाए जाएंगे।

बिल्हौर में फैले 'मकड़जाल' को कौन समेटेगा?

बिल्हौर, शिवराजपुर, ककवन और अरौल मकनपुर से लेकर आसपास के गांवों की गलियों तक निजी क्लीनिकों का ऐसा जाल फैला है, जिस पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। कहीं पंजीकरण अधूरा बताया जाता है, तो कहीं योग्य चिकित्सक की तैनाती को लेकर संशय बना रहता है।चौबेपुर में हुई हालिया कार्रवाई के बाद अब निगाहें बिल्हौर क्षेत्र पर टिक गई हैं। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि जब दूसरे कस्बों में दस्तक दी जा सकती है, तो यहां कब सघन जांच अभियान चलेगा? क्या प्रशासन पूरे नेटवर्क की परतें खोलेगा या फिर यह मुद्दा कुछ दिनों की हलचल के बाद ठंडा पड़ जाएगा?

एक ही जगह बार-बार दिख रहा काला नाग, ग्रामीणों में बढ़ रही आस्था

कुछ श्रद्धालुओं ने मौके पर चढ़ाया दूध, लोगों को सांप से सतर्क रहने की अपील

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। क्षेत्र के बैडी अलीपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत गडरियन पुरवा गांव में पिछले कई दिनों से एक काले नाग के लगातार दिखाई देने से ग्रामीणों में चर्चा और आस्था का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि नाग प्रतिदिन सुबह और शाम गांव को एक खाली पड़े स्थान पर निकलता है और लगभग उसी जगह पर नजर आता है।

नाग के बार-बार एक ही स्थान पर दिखने की घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कई लोग इसे दैवीय संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना बता रहे हैं। नाग को देखने के लिए आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इधर, वन्यजीव जानकारों का कहना है कि यदि किसी स्थान पर सांप को सुरक्षित माहौल और भोजन उपलब्ध होता है तो उसका बार-बार वहीं दिखाई देना सामान्य व्यवहार हो सकता है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और वन विभाग को सूचना देने की सलाह दी है। नाग के दिखने वाले स्थान पर ग्रामीणों ने साफ-सफाई कर अस्थायी पूजा स्थल बनाना शुरू कर दिया है। वहां नियमित रूप से पूजा-अर्चना की जा रही है। महिलाएं दूध, फूल और प्रसाद चढ़ा रही हैं। कई श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के साथ माथा टेक रहे हैं। गांव निवासी अरुण , विजय पाल, राम किशोर, शिवाकांत व अधिवक्ता पंकज समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से लगातार नाग के दर्शन होने से लोगों की आस्था बढ़ी है। फिलहाल गांव में श्रद्धा और उत्सुकता का माहौल बना हुआ है।

सुनसान जगह ले जाकर किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप,पॉक्सो एक्ट में केस

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। ककवन क्षेत्र में सोमवार देर रात 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बताया गया है कि किशोरी मूल रूप से कानपुर देहात की रहने वाली है और ककवन में अपने नाना के यहां रहकर कक्षा सात में पढ़ाई कर रही है। सोमवार रात वह घर के पास स्थित एक दुकान पर पट्टी लेने गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक किशोर ने उसे पकड़ लिया और सुनसान स्थान की ओर ले गया।

परिजनों का आरोप है कि वहां उसके साथ छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की। किसी तरह छूटकर घर पहुंची किशोरी ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे।थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि तहरीर के आधार पर छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

बिल्हौर में बोर्ड परीक्षा के बाद बवाल, छात्राओं ने लगाया पक्षपात से नकल कराने का आरोप

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। बिल्हौर क्षेत्र के खजुरी गांव स्थित अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज में मंगलवार को यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दूसरी पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा समाप्त होते ही बड़ी संख्या में छात्राएं कॉलेज गेट पर इकट्ठा हो गईं। कुछ ही देर में उनके परिजन भी वहां पहुंच गए और माहौल गर्मा गया। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देकर नकल कराई जा रही थी, जबकि अन्य परीक्षार्थियों पर सख्ती बरती गई। उनका कहना था कि कक्ष निरीक्षण के दौरान शौचालय और पानी पीने जैसे बहानों का इस्तेमाल कर कुछ छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। छात्राओं ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष और नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की।

➪ खजुरी के अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज का मामला, गेट पर जुटे अभिभावक

गेट पर प्रदर्शन के दौरान छात्राओं और शिक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। छात्रा का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, हालांकि इसकी पुष्टि आपका अपना स्वराज इंडिया अखबार नहीं करता है। उधर, कॉलेज के प्रधानाचार्य ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही परीक्षा कराई जा रही है और नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन भी सतर्क हो गया।अधिकारियों ने मौके पर जाकर जाँच की । बताया गया कि शिकायत संज्ञान में आई है और एहतियात के तौर पर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि लिखित शिकायत मिलती है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

उड़नदस्ते पर नजर रखने को 'भाड़े के लड़के' तैनात?

सूत्रों का दावा है कि बिल्हौर, अरौल और आसपास के गांवों में संचालित कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय-समय पर नकल कराने की कोशिशें होती रही हैं। चर्चा यह भी है कि उड़नदस्ते की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कथित तौर पर युवकों को मुख्य मार्गों और स्कूल के अहम प्वाइंट्स पर खड़ा किया जाता है। बताया जाता है कि ये युवक अधिकारियों की गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखते हैं। जैसे ही किसी टीम की हलचल दिखती है, मुख्य द्वार पर तैनात कर्मियों तक सूचना पहुंचती है। इसके बाद अंदर मौजूद लोगों को पहले से सतर्क किए जाने की बात कही जाती है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास अचानक सक्रिय हो जाने वाले कुछ चेहरे हर साल दिखाई देते हैं, जिनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि स्वराज इंडिया नहीं करता है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो यह न केवल परीक्षा व्यवस्था पर सवाल है, बल्कि प्रशासनिक निगरानी की चुनौती भी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जिम्मेदार अधिकारी इन चर्चाओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं।

बक्सर में जयमाला के दौरान दुल्हन की गोली मारकर हत्या

» शादी की खुशियां मातम में बदली

» प्रेम प्रसंग के शक में वारदात, आरोपी दीनबंधु फरार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बक्सर। शादी की खुशियों के बीच उस वक्त चीख-पुकार मच गई जब जयमाला की रस्म के दौरान दुल्हन को गोली मार दी गई। मंगलवार रात हुई इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। गंभीर रूप से घायल दुल्हन आरती को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से आई थी। स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन जयमाला की रस्म निभा रहे थे। आसपास परिजन और रिश्तेदार मौजूद थे, म्यूजिक बज रहा था और खुशियों का माहौल था। इसी दौरान चेहरे पर कपड़ा बांधे एक युवक मंच के पास पहुंचा और पिस्तौल से दुल्हन आरती के पेट में गोली मार दी।

गोली लगते ही अफरा-तफरी मच गई। परिजनों के मुताबिक, घायल अवस्था में आरती ने बताया कि उसे दीनबंधु नामक युवक ने गोली मारी है। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

प्रेम प्रसंग का एंगल

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरती की शादी कहीं और तय हो जाने से आरोपी युवक नाराज था और इसी कारण उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी दीनबंधु की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

इस हृदयविदारक घटना से दोनों परिवारों में मातम छा गया है। जहां एक ओर शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहीं अब पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ब्लड प्रेशर चेक न होने पर युवक ने पीएचसी में किया हंगामा

» युवक ने ईट-पत्थरों से की तोड़फोड़, वार्ड बॉय ने थाने में दी तहरीर

अस्पताल परिसर में लगी लोगों की भीड़

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद में मंगलवार को ब्लड प्रेशर चेक कराने आए युवक का चेक न किए जाने पर क्रोधित युवक ने हंगामा काटना शुरू कर दिया परिसर में मौजूद वार्ड बॉय के मना करने पर गाली गलौज करने के साथ ही ईट पत्थर उठाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई ।इस घटना से हजारों रुपये का नुकसान होने अनुमान लगाया जा रहा है। वार्ड बॉय ने आरोपी युवक के खिलाफ शमशाबाद थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

मंगलवार को करीब 2 बजे एक युवक जीशान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनाबाद पहुंचा और वार्ड बॉय से बीपी चेक करने को कहा। फार्मासिस्ट के न होने की बात सुनकर युवक ने क्रोध में आकर गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते हंगामा काटने लगा। वार्ड बॉय के मना करने पर आरोपी ने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इससे स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजों के साथ ही साथ खिड़कियों में लगे शीशे तक टूट गए। बताते है कि आरोपी काफी देर तक अस्पताल में तोड़फोड़ करने से कमरों में रखी जीवन रक्षक दवाइयां जलकर नष्ट हो गई। हंगामा देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ अस्पताल परिसर से फरार हो गया था। पीड़ित वार्ड बॉय ने बताया कि डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना देने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फार्मासिस्ट शैलेंद्र को फोन कर घटना की जानकारी दे दी। साथ ही चिकित्सा प्रभारी शमशाबाद एवं मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद को भी घटना की जानकारी दी गई,घटना के बाद वार्ड बॉय ने आरोपी जीशान के खिलाफ शमशाबाद थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने बात कही है। स्वास्थ्य केंद्र पर हुई इस घटना से कर्मचारियों में दहशत व्याप्त है।

नकली इनहेलर का जाल बेनकाब आगरा में 8 हजार लेबल बरामद

» मशहूर कंपनी के नाम पर फर्जी सप्लाई का शक, प्रदेशभर में नेटवर्क की आशंका

» औषधि विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा, असली फैक्ट्री की तलाश तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

आगरा। नकली दवाइयों और सिरप के मामलों के बीच अब आगरा में नकली इनहेलर का बड़ा खेल सामने आया है। मशहूर दवा कंपनी सिपला के इनहेलर के प्रिंटेड लेबल मिलने से औषधि विभाग में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर नकली इनहेलर तैयार कर प्रदेशभर में सप्लाई की जा रही थी।लखनऊ स्थित औषधि विभाग मुख्यालय की टीम जब सैंपल दवाइयों की कालाबाजारी की जांच के लिए आगरा पहुंची, तो हींग की मंडी निवासी जुबैर खान को पकड़ लिया गया। उसके घर पर छापेमारी के दौरान करीब 8000 प्रिंटेड लेबल बरामद हुए, जो सिपला के फोराकोर्ट इनहेलर के बताए जा रहे हैं।इतनी बड़ी संख्या में लेबल मिलने से साफ है कि यह कोई छोटा नेटवर्क नहीं, बल्कि संगठित स्तर पर नकली इनहेलर तैयार किए जा रहे थे। हालांकि छापे के दौरान घर से पैकिंग या रीफिलिंग का कोई उपकरण नहीं मिला, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्माण का काम किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा था।औषधि विभाग अब उस संभावित फैक्ट्री की तलाश में जुट गया है, जहां इन नकली उत्पादों का निर्माण हो रहा था। तो उसी जगह अन्य दवाओं की नकली तैयारी भी संभव है।बरामद 8000 लेबल की कीमत का अनुमान करीब 20 लाख रुपये लगाया जा रहा है, क्योंकि संबंधित इनहेलर का बाजार मूल्य लगभग 250 रुपये प्रति यूनिट है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सप्लाई केवल आगरा तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे प्रदेश में इसका नेटवर्क फैला हो सकता है।फिलहाल औषधि विभाग मामले की गहन जांच कर रहा है और इस अवैध नेटवर्क के अन्य ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश जारी है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लेकर सख्त दिखे अधिकारी

पात्र युवाओं के आवेदनों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहींः सीडीओ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशासन ने अब रफ्तार तेज कर दी है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि पात्र युवाओं के आवेदनों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, ऋण वितरण की स्थिति और लाभार्थियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की बिंदुवार समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा स्पष्ट है—ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं।

उन्होंने संबंधित विभागों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सभी आवेदनों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

श्री जायसवाल ने लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए और आवेदकों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र युवा इसका लाभ उठा सकें।

साथ ही उद्यम स्थापना के बाद भी लाभार्थियों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और निगरानी उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनके व्यवसाय को स्थायित्व मिल सके और वे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनें।

बैठक में जिला उद्योग विभाग, बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

वीरसेन यादव ने मंगटा गांव पहुंचकर जताया शोक, परिजनों को बंधाया ढांढस

वरिष्ठ समाजसेवी के निधन पर पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सरवनखेड़ा विकास खंड के ग्राम मंगटा निवासी वरिष्ठ समाजसेवी केशव सिंह चौहान के आकस्मिक निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। सोमवार वह स्थानीय पत्रकार सचिन सिंह चौहान के पिता थे।

निधन की सूचना मिलते ही मंगलवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव दिवंगत के आवास पहुंचे। उन्होंने पत्रकार सचिन सिंह चौहान तथा शोकाकुल परिजनों से भेंट कर संवेदना प्रकट की और इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया।उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्व. केशव सिंह चौहान सरल, सौम्य और समाजहित के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने जीवनभर गरीबों और असहायों की सहायता कर क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई। उनके जाने से परिवार ही नहीं, पूरे क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि समाजवादी परिवार हर परिस्थिति में चौहान परिवार के साथ खड़ा रहेगा। मंगल सिंह परिहार, सुजीत पाल (जिला उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग), विरेंद्र सिंह चौहान, मोहित गुप्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।

सफाईकर्मियों ने वेतन के नाम पर वसूली का आरोप लगाया

» सहकर्मी पर अभद्रता और स्थानांतरण न मानने का आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकास खंड अकबरपुर के सफाईकर्मियों ने अपने सहकर्मी ज्ञान प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। सफाईकर्मियों का कहना है कि ज्ञान प्रकाश की नियुक्ति ग्राम राजस्व गांव मुक्तापुर में हुई थी, लेकिन पिछले साढ़े चार वर्षों से वह विकास खंड कार्यालय में ही संबद्ध रहकर कार्य कर रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ज्ञान प्रकाश ब्लॉक कार्यालय में बैठकर कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने समर्थकों से गाली-गलौज भी करवाते हैं। इस संबंध में सभी सफाईकर्मियों ने 19 जनवरी 2026 को जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर देहात को स्टांप पर शिकायत दी थी।

बताया गया कि उस शिकायत के आधार पर अधिकारी ने ज्ञान प्रकाश को विकास खंड से हटाकर ग्राम पंचायत पुर में भेजने के निर्देश दिए थे। हालांकि, उन्होंने अब तक संबंधित ग्राम में योगदान नहीं किया है। सफाईकर्मियों ने सवाल उठाया है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी उन्होंने ग्राम में कार्यभार ग्रहण क्यों नहीं किया।

सफाईकर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि वेतन जारी कराने के नाम पर उनसे 1000 से 1500 रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है। आरोप है कि ग्राम प्रधानों से कहकर वेतन मांगपत्र जानबूझकर देर से बनवाया जाता है। जब कर्मचारी मांगपत्र जमा करने आते हैं, तो उनसे धनराशि की मांग की जाती है। यदि कोई कर्मचारी सीधे कार्यालय में जाकर मांगपत्र जमा करता है, तो उसे संबंधित लिपिक के खिलाफ शिकायत करने की धमकी दी जाती है।हालांकि, सफाईकर्मियों ने स्पष्ट किया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उनसे किसी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाती है।

सभी सफाईकर्मियों ने मांग की है कि ज्ञान प्रकाश को तत्काल ग्राम पंचायत में योगदान कराया जाए। साथ ही, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं, ताकि वेतन मांगपत्र बनाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

बेटे की हत्या में महिला को उम्रकैद, 25 हजार का जुर्माना

कहासुनी के बाद अभियुक्ता ने वादिनी के पुत्र की हत्या कर दी थी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। करीब तीन वर्ष पुराने हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जनपद के ग्राम बरईझाल, थाना रसूलाबाद थाना निवासी रिहाना पत्नी अरमान को एडीजे (एफटीसी) न्यायालय, कानपुर देहात ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ?25 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

16 फरवरी 2023 की थी घटना

अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 फरवरी 2023 को कहासुनी के बाद अभियुक्तों ने वादिनी के पुत्र की हत्या कर दी थी। मामले में थाना रसूलाबाद में धारा 302/201 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

प्रभावी पैरवी से मिली सजा

पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्र कर समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्ता को दोषी ठहराया। ऑपरेशनहुकन्विक्शन के तहत पुलिस व अभियोजन की सतत पैरवी के चलते मामले में दोष सिद्ध हुआ। अदालत के इस निर्णय को कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रसूलाबाद में पुलिस की चौकसी तेज, कस्बों में पैदल गश्त

असालतगंज में कोतवाल शिव नारायण सिंह ने व्यापारियों से किया संवाद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात (रसूलाबाद) कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से रसूलाबाद पुलिस ने कस्बों में चौकसी तेज कर दी है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा का एहसास करा रही है।असालतगंज कस्बे में कोतवाल शिव नारायण सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की और व्यापारियों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था का पालन करना पुलिस का नैतिक दायित्व है। क्षेत्र में अराजकता फैलाने या कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रसूलाबाद कोतवाली का प्रभार संभालने के बाद से ही कोतवाल शिव नारायण सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उन्होंने रसूलाबाद कस्बे में भी व्यापारियों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया था। अब चौकी क्षेत्रों में भी नियमित पैदल गश्त शुरू कर दी गई है। कोतवाल ने बताया कि बेहतर पुलिसिंग के जरिए आमजन में विश्वास कायम करना प्राथमिकता है। सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गुप्तचर तंत्र भी सक्रिय कर दिया गया है, जो क्षेत्र की सूचनाएं पुलिस तक पहुंचा रहा है। चौकी प्रभारी केशव देव, दीवान ज्ञानवीर सिंह सहित कई आरक्षी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

श्रीमद्भागवत कथा के समापन पर धनश्वर धाम में भंडारा का लिया प्रसाद

» सात दिन तक चली कथा में उमड़ा आस्था का सैलाब

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।रसूलाबाद क्षेत्र के पावन स्थल श्री धनेश्वर धाम में आयोजित सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कथा के विराम दिवस पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आया।सात दिनों तक चली भक्तिमयी कथा में आचार्य कृष्णानंद रसिक ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं एवं भागवत महात्म्य का भावपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबोए रखा। कथा के अंतिम दिन वातावरण 'राधे-राधे' और 'जय श्रीकृष्ण' के उद्घोष से गूंज उठा।कथा के उपरांत दोपहर बाद प्रारंभ हुआ भंडारा देर रात तक चलता रहा। आसपास के गांव—मुर्री, रसूलपुर, महबूबपुर, मक्कानिवादा, तिश्ती, बारापुर, धरमपुर सहित कई स्थानों से पहुंचे भक्तों ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। खीर, पूरी और सब्जी का प्रसाद श्रद्धा और प्रेम से वितरित किया गया।पूरा आयोजन भक्ति, सेवा और सहयोग की भावना से सम्पन्न हुआ। आयोजन समिति एवं क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के सहयोग से व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रही। धनेश्वर धाम में उमड़ी भीड़ और भक्तों की आस्था ने कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान किया। धार्मिक आयोजन ने क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया मन में भक्ति की अलख जगाई।

कहिंजरी की धड़कन: 150 वर्ष पुराना भव्य राधा-कृष्ण मंदिर

» अनोखी दीवार कला, अनुशासित परंपराएं और जन्माष्टमी की अनुपम छटा से आलोकित रसूलाबाद का आस्था-धाम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गांवों की मिट्टी में जब इतिहास और भक्ति का संगम होता है, तब वहां केवल इमारतें नहीं, बल्कि जीवंत आस्थाएं खड़ी होती हैं। रसूलाबाद क्षेत्र के कहिंजरी स्थित भीखदेव बाजार में स्थित करीब डेढ़ सौ वर्ष पुराना राधा-कृष्ण मंदिर, कहिंजरी ऐसा ही एक पावन स्थल है, जहां प्रवेश करते ही श्रद्धा स्वयं शीश झुका देती है।

स्थानीय जनश्रुति के अनुसार इस भव्य मंदिर का निर्माण सेठ राम नारायण उर्फ मनइया सेठ ने कराया था। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई बारीक और मनोहारी कलाकृतियां तत्कालीन रियासती शैली की समृद्ध झलक प्रस्तुत करती हैं। नक्काशी की सूक्ष्मता और अलंकरण की गरिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो पत्थरों पर इतिहास ने स्वयं अपने हस्ताक्षर अंकित किए हों।

जन्माष्टमी पर उमड़ता है श्रद्धा का सागर

हर वर्ष जन्माष्टमी पर यहां भक्ति का विराट उत्सव सजता है। पखवारे भर भजन-कीर्तन, झांकियां और धार्मिक अनुष्ठानों की मधुर ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना देती है। दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं और पूरा क्षेत्र कृष्णमय हो उठता है। मंदिर की देखरेख कर रहे सुब्रत गुप्ता बताते हैं कि इस अवसर पर आस्था का ऐसा संगम होता है, जिसमें हर हृदय भावविभोर दिखाई देता है। वहीं पुजारी रामपाल शुक्ला के अनुसार गर्भगृह में स्थापित विग्रहों का चित्र लेना पूर्णतः निषिद्ध है। स्थापना काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी अक्षुण्ण है, जो इस धाम की विशिष्ट मर्यादा को दर्शाती है।

वामन द्वादशी पर जल-विहार की परंपरा

जन्माष्टमी के अतिरिक्त वामन द्वादशी पर भी यहां तीन दिवसीय विशेष आयोजन होता है। भगवान वामन का डोला श्रद्धालु कंधों पर उठाकर शोभायात्रा के साथ राम तलैया तक ले जाते हैं, जहां विधिवत जल-विहार संपन्न होता है। अनंत चतुर्दशी को इस उत्सव का भावपूर्ण समापन किया जाता है। कहिंजरी कस्बा अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए है, परंतु यह राधा-कृष्ण मंदिर अपनी अद्वितीय दीवार कला, अनुशासित परंपराओं और सतत जीवंत धार्मिक आयोजनों के कारण विशेष आभा बिखेरता है। यहां इतिहास केवल अतीत नहीं, बल्कि आज भी धड़कती हुई आस्था के रूप में विद्यमान है।

अलीगढ़:नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी

सपाइयों के दबाव में नहीं झुके नगर निगम अधिकारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अलीगढ़। नगर निगम अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद राजनीति गरमा गई है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान फल विक्रेताओं द्वारा निगम टीम पर हमला किया गया था, जिसमें सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता,कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंच गए।

मंगलवार को सपा, बसपा और कांग्रेस से जुड़े लोग नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा पर मुकदमा वापस लेने तथा सुरक्षाकर्मी पर कार्रवाई करने को दबाव बनाने की कोशिश की।

इस दौरान सपा नेता अज्जू इशाक ने नगर आयुक्त के साथ अभद्र व्यवहार व बदसलूकी भी किया।

नहीं झुके नगर आयुक्त

नगर आयुक्त ने पूरी संयम और गरिमा के साथ स्थिति को संभाला और स्पष्ट कर दिया कि कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी और किसी भी दबाव में गलत फैसला नहीं लिया जाएगानगर आयुक्त के इस रुख की प्रशासनिक हलकों में सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

इस विवाद को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि इन दुकानदारों को विगत अगस्त महीने से लगातार नोटिस दिया जा रहा था,इन्हें कहा जा रहा था कि नगर निगम द्वारा वेंडिंग ज़ोन में अपनी व्यापारिक गतिविधि संचालित करें,लेकिन इनका मनमाना रवैया जारी था।

प्रशासन द्वारा 6 महीने की नोटिस के बाद ही यह कार्रवाई की गई।

सपा नेताओं द्वारा नगर आयुक्त के साथ किये गए दुर्व्यवहार को लेकर अब कहा जा रहा है सपा नेता अज्जू इशाक समेत लोगों की मुश्किलें बढ़नी तय है।

नगर निगम का दावा नियमों के हिसाब से कार्रवाई

नगर निगम अधिकारी ने बताया कि तसवीर महल क्षेत्र में फुटपाथ और सड़क तक पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे राहगीरों और वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी. उन्होंने मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई नियमानुसार की गई और यदि किसी कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया है, तो उसकी जांच कराई जाएगी. नगर निगम का दावा है कि अतिक्रमण हटाने से पहले कई बार चेतावनी दी गई थी. अधिकारियों का कहना है कि अभियान शहरभर में चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य केवल सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराना है. उन्होंने यह भी कहा कि फुटपाथ पर व्यापार करना नियमों के विरुद्ध है और इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है.

धर्म, कानून और राजनीति के चौराहे पर खड़ा उत्तर प्रदेश !

प्रयागराज के झूंसी थाना में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर से सियासत गरम

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ अदालत के आदेश पर झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहराई से महसूस किया जा रहा है। आरोप गंभीर हैं और एफआईआर में पॉक्सो एक्ट सहित कड़ी धाराएं लगाई गई हैं, जिससे यह प्रकरण सूबे की सियासत के केंद्र में आ गया है। पॉक्सो कानून बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में देश का सबसे सख्त कानून माना जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में लगभग 54,000 पॉक्सो मामले दर्ज हुए थे। इनमें से करीब 7,500 मामले उत्तर प्रदेश से थे, जो कुल मामलों का लगभग 14 प्रतिशत है। इन मामलों में लगभग 65 प्रतिशत पीड़ितों की उम्र 16 वर्ष से कम पाई गई।

औसतन देखें तो यूपी में प्रतिदिन 20 से अधिक पॉक्सो मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में किसी बड़े धार्मिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना असाधारण घटना माना जा रहा है।

शंकराचार्य ने आरोपों को बताया साजिश

» एफआईआर अब केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं यह प्रदेश की राजनीति में धर्म, सत्ता और जनभावनाओं के टकराव का बड़ा प्रतीक बन चुकी है

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सुनियोजित साजिश बताया है। उनका कहना है कि शिकायत में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है,

वे कथित तौर पर 15 से 20 वर्ष पुरानी बताई जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लंबे समय बाद मामला सामने आने के पीछे क्या कारण हैं।

उन्होंने कहा कि उनके गुरुकुल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जांच एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जांच से भागेंगे नहीं और कानून का सामना करेंगे।

सियासी घमासान: सपा का खुला समर्थन

मामले ने राजनीतिक रंग तब लिया जब समाजवादी पार्टी खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में सामने आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एफआईआर को सरकार की नीयत से जोड़ते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जो सरकार स्वयं को सनातन धर्म की रक्षक बताती है, वही आज धर्म के प्रतिष्ठित पद पर बैठे संत को झूठे आरोपों में घसीट रही है।

अखिलेश यादव ने इसे केवल धार्मिक या कानूनी मुद्दा मानने से इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। सपा के आंतरिक आकलन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगभग 12 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत के आसपास है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में पिछले तीन वर्षों में औसतन 25 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। सपा का तर्क है कि ऐसे संवेदनशील मामलों से सरकार के खिलाफ जनभावना और तेज हो सकती है।

सरकार का रुख :कानून सबके लिए समान

सरकार और भाजपा समर्थकों का कहना है कि एफआईआर अदालत के आदेश पर दर्ज हुई है और पुलिस केवल न्यायिक निर्देशों का पालन कर रही है।

उनका तर्क है कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धार्मिक या सामाजिक पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट और विस्तृत राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है।

संत समाज बंटा, निष्पक्ष जांच की मांग

धार्मिक जगत में भी इस प्रकरण को लेकर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। संत समाज का एक वर्ग इसे सनातन परंपरा पर हमला बता रहा है और शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा है। वहीं कुछ धार्मिक संगठनों का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और निष्पक्ष व पारदर्शी जांच आवश्यक है।

आंकड़ों के अनुसार, यूपी में दर्ज पॉक्सो मामलों में लगभग 9 से 10 प्रतिशत मामलों में आरोपी सामाजिक रूप से प्रभावशाली या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पाए गए हैं, जिससे ऐसे मामलों में विवाद और राजनीतिक दबाव बढ़ जाता है।

2027 चुनाव से पहले बढ़ेगा सियासी तापमान

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित मुद्दे हमेशा चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण की बड़ी भूमिका रही थी।

अब जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है, ऐसे मामलों का प्रभाव धीरे-धीरे जमीन पर दिखाई दे सकता है।

सपा इसे संतों के अपमान और सरकार की कथित दमनकारी नीति के रूप में पेश कर रही है,

जबकि भाजपा इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताकर राजनीतिक आरोपों से दूरी बना रही है।

फिलहाल मामला जांच के शुरुआती चरण में है। कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है और अंतिम निष्कर्ष आने में समय लगेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज एफआईआर अब केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं रह गई है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, सत्ता और जनभावनाओं के टकराव का बड़ा प्रतीक बन चुकी है।

आने वाले महीनों में जांच की दिशा और नए तथ्यों के सामने आने के साथ इस प्रकरण का राजनीतिक तापमान और बढ़ सकता है, जिसका असर प्रदेश की सियासत पर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा।

नगर निगम की ट्रैक्टर खरीद में गुजरात कनेक्शन, 46 लाख की डील पर सवाल

डेढ़ हजार किमी दूर वलसाड़ से खरीद, जेम बिड और पसंदीदा कंपनी पर उठे संदेह

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या नगर निगम की ट्रैक्टर खरीद में अब गुजरात कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मच गया है। नगर निगम ने करीब डेढ़ हजार किलोमीटर दूर स्थित वलसाड़ जिले की एक फर्म से आठ ट्रैक्टर खरीदे हैं, जिस पर लगभग 46 लाख रुपये का भुगतान किया गया। सूत्रों के अनुसार यह खरीद वलसाड़ स्थित किसान फोर्स फर्म से की गई है। इनमें स्वराज कंपनी के 35.3 हॉर्स पावर के छह और 45 हॉर्स पावर के दो ट्रैक्टर शामिल हैं। इनवायस नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गुरुप्रसाद पांडेय के नाम जारी हुआ है। नगर निगम के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रदेश में कई अधिकृत विक्रेता मौजूद हैं, तो इतनी दूर से खरीद का औचित्य क्या था।

अधिकारियों की ओर से ढुलाई भाड़ा कम पड़ने और प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से होने की दलील दी जा रही है।

हालांकि चर्चा यह भी है कि बिड में केवल स्वराज ट्रैक्टर की मांग रखकर अन्य कंपनियों को बाहर कर दिया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा की संभावना खत्म हो गई। अगर महिंद्रा, एस्कॉर्ट या सोनालिका जैसी कंपनियों को शामिल किया जाता, तो कीमतें और कम हो सकती थीं। अब नगर निगम के भीतर और बाहर इस सौदे को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी और व्यापारी वर्ग इस ÷गुजरात कनेक्शन÷ के पीछे की सच्चाई जानने में जुटा है। मांग उठ रही है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। सहायक नगर आयुक्त का कहना है कि यह खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है इसमें कोई अनियमित नही है।

मुसहर जाति का प्रमाणपत्र बना, लिया सरकारी लाभ

डेढ़ साल बाद मानी गलती, लेखपाल पर कार्रवाई से बचते रहे तहसीलदार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या की बीकापुर तहसील एक बार फिर विवादों में है। यहां पाराहथिगो गांव के कुछ लोगों को त्रुटिवश मुसहर जाति का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया, जबकि वे वास्तव में वनमानुष जाति के बताए जा रहे हैं। यह प्रमाणपत्र 10 जुलाई 2024 को जारी हुआ, लेकिन तहसीलदार ने इसकी गलती फरवरी 2026 में आईजीआरएस आख्या में स्वीकार की। सबसे गंभीर सवाल यह है कि डेढ़ वर्ष की अवधि में इन प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी योजनाओं का कितना लाभ लिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, इन प्रमाणपत्रों का उपयोग मुख्यमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता पाने के लिए किया गया। आरोप है कि हल्का लेखपाल की रिपोर्ट पर बिना सत्यापन कई प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि आईजीआरएस निस्तारण भी उसी लेखपाल के बयान पर कर दिया गया, जिस पर आरोप हैं। तहसीलदार अब तक किसी ठोस कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं।

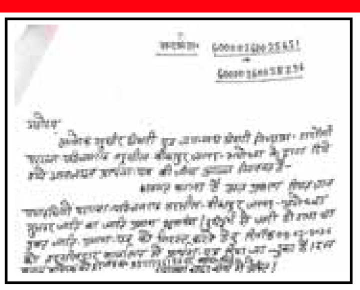

मामले में ग्राम पंचायत से लेकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तक सेटिंग का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता सुधीर तिवारी का कहना है कि यह गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित घोटाला है।

अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा?

मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी, रामपथ के विस्थापित व्यापारियों से खुली लूट!

ब्याज मुक्त किस्तों का वादा टूटा, विकास प्राधिकरण पर मनमानी के गंभीर आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को विश्वस्तरीय नगरी बनाने के लिए अरबों रुपये खर्च किए, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है। रामपथ और आसपास से विस्थापित दुकानदारों को 20 वर्षों तक ब्याज मुक्त किस्तों पर दुकान देने की घोषणा के बावजूद अब तक इसका लाभ नहीं मिला।व्यापारियों का आरोप है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर दुकानों के मूल्य में हर वर्ष 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी। 2023 में आवंटित दुकानों पर मूल दर ली गई, जबकि 2024 और 2025 में बढ़ी हुई कीमत वसूली गई, जिससे व्यापारी आर्थिक बोझ तले दब गए। दुकानदारों का कहना है कि आवंटन में देरी शासन की जांच प्रक्रिया के कारण हुई, फिर भी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। आवंटन पत्र में मूल्य वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं था, इसके बावजूद अतिरिक्त वसूली की गई। अब पीड़ित व्यापारी मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सरकारी वादों की खुली अवहेलना भी है।

राम मंदिर से लेकर पूरे अयोध्याधाम पर रहेगी 24 घंटे डिजिटल नजर

रामनगरी की सुरक्षा का नया कवच, हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर और पूरे अयोध्याधाम की निगरानी के लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम लगभग तैयार हो चुका है, जो आने वाले दिनों में अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। इस आधुनिक कमांड सेंटर से पूरे परिसर की रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी।

संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को यहीं से निर्देश मिलेंगे।

कंट्रोल रूम के निर्माण में अब केवल बाहरी हिस्से में बिजली से जुड़े कार्य शेष हैं। इसके लिए कार्यदायी संस्था ने शासन से 50 लाख रुपये की मांग की है। बजट मिलते ही कार्यों को तेजी से पूरा कर मार्च तक भवन को पुलिस विभाग को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कंट्रोल रूम आतंकी खतरे, भीड़ प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट की निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा।

क्राइम पत्रिका की पड़ताल में सामने आया है कि यह केंद्र न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा रीढ़ बनने जा रहा है। रामनगरी अब तकनीक के सहारे खुद को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुकी है।

होली के बाद पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी

तीन डीजी 28 फरवरी को होंगे रिटायर, कई एडीजी को प्रमोशन और बड़े स्तर पर तबादले संभावित

स्वराज इंडिया ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में होली के बाद बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी है। वरिष्ठ स्तर पर होने वाली सेवानिवृत्तियों के चलते डीजी और एडीजी रैंक में व्यापक फेरबदल तय माना जा रहा है। शासन स्तर पर संभावित प्रोन्नतियों और नई तैनातियों को लेकर मंथन चल रहा है।

28 फरवरी को डीजी मानवाधिकार संदीप सालुंके, डीजी होमगार्ड एमके बशाल और डीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन तीनों अधिकारियों के रिटायर होने से डीजी स्तर के महत्वपूर्ण पद रिक्त हो जाएंगे।

इन रिक्तियों को भरने के लिए तीन एडीजी रैंक के अधिकारियों को डीजी पद पर प्रोन्नत किए जाने की तैयारी है। प्रस्तावित नामों में एडीजी रेलवे प्रकाश डी, एडीजी रूल्स एंड मैनुअल एलवी एंटनी देव कुमार और एडीजी पावर कॉरपोरेशन जय नारायण सिंह प्रमुख बताए जा रहे हैं। प्रोन्नति के बाद इन अधिकारियों को मानवाधिकार, होमगार्ड, अभियोजन या अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

इसके साथ ही 30 अप्रैल को डीजी यूपी-112 एवं आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की प्रमुख नीरा रावत भी सेवानिवृत्त होंगी। उनकी रवानगी के बाद यूपी-112 जैसी अहम आपातकालीन सेवा और ईओडब्ल्यू में भी नई तैनाती होगी, जिससे एक और बड़े स्तर का प्रशासनिक पुनर्गठन संभव है।

सूत्रों के मुताबिक कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह का नाम भी डीजी पद पर संभावित प्रोन्नति की सूची में शामिल है। यदि उन्हें पदोन्नति मिलती है तो जोनल स्तर पर भी नई नियुक्ति करनी होगी, जिससे कई जिलों में पुलिस नेतृत्व बदलेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति और तबादलों की इस श्रृंखला का असर पुलिस मुख्यालय से लेकर जोन, रेंज और जिला स्तर तक दिखाई देगा। शासन जल्द ही औपचारिक आदेश जारी कर सकता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक संतुलन, वरिष्ठता और रिक्त पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

कुल मिलाकर होली के बाद पुलिस महकमे में नेतृत्व के स्तर पर बड़ा बदलाव तय है, जिससे कई अहम शाखाओं और जोनों में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

यूएन में युद्धविराम प्रस्ताव पारित भारत ने फिर साधी तटस्थता

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर पेश किया गया एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 107 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत ने एक बार फिर मतदान में हिस्सा नहीं लेकर अपना तटस्थ रुख बरकरार रखा।

प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्धविराम (सीजफायर) की मांग की गई है। इसे वैश्विक स्तर पर शांति बहाली की दिशा में एक अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर भी जोर दिया गया है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय स्थायी शांति, पूर्ण युद्धविराम और विस्थापित यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज़ेलेंस्की के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन यह संकेत देता है कि दुनिया युद्ध की समाप्ति चाहती है।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध की चौथी बरसी के मौके पर इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष जितना लंबा चलेगा, उतना ही विनाशकारी सिद्ध होगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ रहा है। गुटेरेस ने दोहराया कि शांति प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का पूर्ण सम्मान अनिवार्य है।

➪ **107 देशों का समर्थन, रूस-यूक्रेन संघर्ष पर तत्काल और बिना शर्त सीजफायर की मांग**

भारत का संतुलित रुख कायम

भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाकर अपनी पूर्व घोषित नीति को दोहराया है। भारत लगातार संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान पर जोर देता रहा है। नई दिल्ली का मानना है कि स्थायी शांति का रास्ता प्रत्यक्ष वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह रुख उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है, जिसमें वह किसी भी पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होने से बचते हुए शांति प्रयासों का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव के पारित होने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से युद्धविराम के लिए दबाव बढ़ा है, हालांकि जमीन पर संघर्ष की स्थिति और दोनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताएं आने वाले समय में इसकी वास्तविक प्रभावशीलता तय करेंगी।

पाकिस्तान में 70 वर्षीय हकीम ने 22 साल की युवती से रचाई शादी

उम्र के फासले पर मचा बवाल, दंपती बोले- "उम्र सिर्फ एक नंबर"

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न एक शादी सोशल मीडिया पर तीखी बहस का विषय बन गई है। करीब 70 वर्षीय हकीम बाबर ने 22 वर्षीया युवती से निकाह किया है। दोनों के बीच लगभग 48 वर्ष का अंतर होने के कारण यह विवाह इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं।

पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जब मीडिया प्रतिनिधि हकीम बाबर के घर पहुंचे तो नवविवाहित जोड़े ने खुलकर बातचीत की। शादी को लेकर उठ रहे सवालों पर दूल्हे ने कहा कि ÷उम्र केवल

एक संख्या है, रिश्ते आपसी समझ और सहमति पर आधारित होते हैं।÷ दुल्हन ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा कि उनके फैसले को निजी दायरे में देखा जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस विवाह को असामान्य बताते हुए आलोचना की, वहीं कई उपयोगकर्ताओं ने इसे व्यक्तिगत पसंद का मामला कहा। दंपती ने आलोचकों पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी जोड़े के बीच उम्र के अंतर को आधार बनाकर निर्णय देना उचित नहीं है।

नवदंपती ने बताया कि वे ईद के बाद उमराह के लिए सऊदी अरब जाने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद हनीमून के लिए नीदरलैंड्स यात्रा का कार्यक्रम भी तय किया गया है। यह शादी फिलहाल पाकिस्तान में सामाजिक विमर्श का विषय बनी हुई है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के बीच संतुलन को लेकर बहस जारी है।

भारत-इजरायल रणनीतिक समीकरण से पाकिस्तान में हलचल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और इज़रायल के बीच तेज़ी से गहराते रणनीतिक रिश्तों ने दक्षिण एशिया और मध्य-पूर्व की कूटनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। हालिया घटनाक्रमों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित कथित 'हेक्सागन अलायंस' की अवधारणा और नरेंद्र मोदी के साथ बढ़ते समन्वय को लेकर पाकिस्तान ने औपचारिक आपत्ति दर्ज की है।

पाकिस्तान की सीनेट ने 24 फरवरी को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर इस संभावित बहुपक्षीय गठबंधन पर चिंता जताई। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत-इज़रायल की बढ़ती सामरिक निकटता क्षेत्रीय संतुलन और 'मुस्लिम देशों की एकजुटता' को प्रभावित कर सकती है।

इज़रायली मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, 'हेक्सागन अलायंस' छह देशों का

➪ **पाक सीनेट का प्रस्ताव; 'हेक्सागन अलायंस' की अवधारणा पर तीखी प्रतिक्रिया**

एक संभावित मंच हो सकता है, जिसका उद्देश्य उग्रवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटने के लिए सुरक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग को संस्थागत रूप देना है। इसमें भारत, इज़रायल, ग्रीस, साइप्रस तथा कुछ उदारवादी अरब व अफ्रीकी देशों की संभावित भागीदारी की चर्चा है। हालांकि, इस गठबंधन को लेकर अभी कोई औपचारिक बहुपक्षीय घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रस्तावित ढांचे ने क्षेत्रीय कूटनीति में हलचल तेज कर दी है। भारत-इज़रायल संबंध पिछले एक दशक में रक्षा, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, मिसाइल प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। भारत पहले से ही इज़रायली वायु रक्षा प्रणालियों, सटीक-निर्देशित हथियारों और निगरानी तकनीकों का प्रमुख आयातक रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देश सहयोग को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाते हैं, तो यह सहयोग केवल रक्षा खरीद तक सीमित न रहकर संयुक्त अनुसंधान, उत्पादन और खुफिया साझेदारी तक विस्तृत हो सकता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com